

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का निष्पाक है और कौन कानून का निर्माता"-वेडेल फिलिपा

भारतीय बस्ती

बस्ती 16 सितम्बर 2024 सोमवार

सम्पादकीय

हाशिये पर लोकपाल

भ्रष्टाचार पूरी दुनिया के सामने विकास और खुशहाली की राह में बहुत बड़ा रोड़ा है। इसलिए लगभग हर देश ने इस पर अंकुश लगाने का तंत्र विकसित कर रखा है। प्रशासन की जवाबदेही तय करने की कोशिशें की जाती हैं। मगर हमारे यहां इस मामले में ज्यादातर नाकामी ही नजर आती है। इसलिए लंबे समय से मांग की जाती रही कि लोकपाल और लोकायुक्त के गठन संबंधी कानून बनना चाहिए। करीब ग्यारह वर्ष पहले इसे लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके दबाव में लोकपाल अधिनियम पारित हुआ। मगर लोकपाल की नियुक्ति का मामला करीब पांच वर्ष तक इस तर्क के आधार पर टलता रहा कि लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं था। लोकपाल अध्यक्ष की नियुक्ति में विपक्ष के नेता का होना जरूरी है।

अखिरकार पांच वर्ष पहले लोकपाल का गठन हुआ, मगर अभी तक वह पूरी तरह कार्य करने की स्थिति में नहीं आ सका है। अब लोकपाल के जांच प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ में लोकपाल अध्यक्ष के अधीन एक जांच निदेशक होगा, जिसे तीन पुलिस अधीक्षक मदद करेंगे। प्रत्येक पुलिस अधीक्षक को जांच अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की सहायता प्रदान की जाएगी। इस तरह उम्मीद बनी है कि अब लोकपाल की अनियमितताओं के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए जा सकेंगे।

हालांकि भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत पहले से कई जांच एजेंसियां काम करती हैं। हर महकमे के कर्मचारी पर वहां का सतर्कता विभाग नजर रखता और उसके खिलाफ शिकायतों का निपटारा करता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग भी संबंधित मामलों में जांच करते हैं। मगर प्रशासनिक सुधार आयोग का मानना था कि लोकपाल और लोकायुक्त के गठन से लोकरसेवकों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो सकेगी।

दूसरी जांच एजेंसियों पर चूँकि राजनीतिक प्रभाव अधिक देखा गया है, इसलिए उनसे भ्रष्टाचार के मामले में निष्पक्षता की उम्मीद धुंधली बनी रहेगी। पर शायद सरकारों को पैदा होती रही कि उसके दायरे में प्रधानमंत्री तक को रखा गया है। फिर, लोकपाल और लोकायुक्त संतंत्र निकाय की तरह काम करेंगे, उन्हें दूसरी एजेंसियों की तरह किसी अडि कारी के खिलाफ जांच करने के लिए संबंधित विभाग से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। कई सरकारों को लगता रहा है कि इस तरह उनके कामकाज में बाधा पड़ सकती है। शायद यही कारण है कि अब भी कई राज्य सरकारों ने अपने यहां लोकायुक्त का गठन नहीं किया है।

देर से ही रही, लोकपाल के जांच प्रकोष्ठ के गठन से लोगों में भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में उल्लेखनीय नतीजों की उम्मीद जगी है। लोकसेवकों में गलत तरीके से पैसा कमाने की भूख और रिश्तत लेकर अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने, सरकारी योजनाओं में गतिरोध और छीजन पैदा करने की प्रवृत्ति किसी से छिपी नहीं है। इस वातावरण को तनी ठीक किया जा सकता है, जब लोकसेवकों की अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सके।

भारत में भ्रष्टाचार व्यक्तिगत स्तर से कहीं आगे तक फैला हुआ है और लगभग हर संस्थान में पाया जा सकता है। इसलिए, व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए कानून के तहत इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कारण देश में एक वातावरण बना किन्तु विसंगति ही है कि अभी तक मोदी सरकार में यह प्रभावी नहीं हो सका है। लोकपाल विधेयक के लिए अन्ना हजारे का आह्वान और उनका भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, भ्रष्टाचार की बढ़ती लहर के विरुद्ध एक चमत्कार सितारा था। यह स्वप्न कब साकार होगा यह यक्ष प्रश्न है।

हालांकि कुछ लोग यह संशय व्यक्त करते रहे हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति में भी राजनीतिक दखल होती है, इसलिए वे कितने निष्पक्ष रहे पाएंगे, कहना मुश्किल है। मगर एक विशाल जनसमुदाय और बड़े प्रतिबद्ध प्रयुद्ध समाज की इच्छा से गठित इस संस्था से भ्रष्टाचार निवारण को लेकर निष्ठा और निष्पक्षता की उम्मीद फिलहाल कमजोर नहीं हुई है।

राहुल गांधी से नफरत के निहितार्थ



-तनवीर जाफरी-

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रखने वाले किसी भी देश में सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक गाड़ी के दो पहियों के समान माने जाते हैं। सत्ता का काम जहां देश के लिये नीतियां व योजनाएं बनाना होता है वहीं विपक्ष का काम सत्ता की कार्रगुजारियों पर निगरानी रखना होता है। विपक्ष जरूरत पड़ने पर समय समय पर सत्ता की अलोचना भी करता रहता है। और सत्ता उन स्वस्थ अलोचनाओं का स्वागत करते हुये विपक्ष की अलोचना के अनुकूल अपनी नीतियों व योजनाओं में परिवर्तन व संशोधन करने का भी प्रयास करती है। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश में सत्ता और विपक्ष के रिश्ते प्रायः भ्रूय व डॉम मनीहार जवाहर लाल नेहरू व डॉम मनमोहन लोहिया तथा राजीव गांधी, सोनिया गांधी व अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अफेक शीर्ष नेताओं के ऐसे कड़े रिश्ते बड़े महत्त्व हैं जो एक विपक्ष के सौहार्दपूर्ण रिश्तों की गवाही देते हैं।

परन्तु वर्तमान दौर की राजनीति में तो गोया सत्ता द्वारा विपक्ष से दुश्मन की तरह व्यवहार किया जा रहा है। इस मामले में डॉम मनीहार लोहिया व डॉम मनमोहन लोहिया का नाम भी खाली करना पड़ता है। देश में यह भी देखा कि किस तरह राहुल गांधी व उनकी मां सोनिया गांधी को कई दिनों तक बार बार प्रवर्तन निदेशालय (ई डी) द्वारा अपने कार्यालय में बुलाकर उनका



फरोखत कर निर्वाचित सरकार निकाल, मीडिको को पोलम बनाकर गोया किसी भी तरह से यह कोशिश की जाने लगी है कि विपक्ष का नामो निशान खत्म कर दिया जाय और सत्ता पर हमेशा के लिये कब्जा जमाये रखा जाय। सत्ता के इस लोकतंत्र विरोधी कहे जाने वाले दुष्प्रयास का सबसे बड़ा निशाना लोकसभा में प्रविष्टि के नेता राहुल गांधी हैं। पिछली लोकसभा में यह देखा गया कि किस तरह एक अन्तर्लाली फसले की आड़ लेकर आनन फानन में उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गयी और सदस्यता समाप्त करने के साथ ही सांसद के रूप में आवांटी किया गया उनका बंगला भी खाली करा दिया गया। देश में यह भी देखा कि किस तरह राहुल गांधी व उनकी मां सोनिया गांधी को कई दिनों तक बार बार प्रवर्तन निदेशालय (ई डी) द्वारा अपने कार्यालय में बुलाकर उनका

मनोबल गिराने की कोशिश की गयी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का बैक खाता परीज कर दिया गया। पिछले दस वर्षों से राहुल गांधी को 'पप्पू' साबित करने के लिये करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाये गये। मीडिया का सहारा लेकर राहुल को कष्टप्रदे में खड़ा करने की कोशिशें की गयीं। इद तो यह है कि संसद में स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राहुल गांधी को 'बाल बुद्धि' वाला कहकर सम्बोधित किया गया? संप्रदाय विशेष को 'जूले मारो सालों को' जैसा उल्लेखनात्मक नारा देना वाला एक परिश्रवार्थी राजनीति का प्रतीक भाजपा नेता संसद में राहुल की जाति पर सवाल खड़ा करते दिखाई दिया।

और अब एक बार फिर राहुल की अमेरिका यात्रा में दिए गए उनके कुछ बयानों को साबित उनकी 'देशद्रोही' तक लाकर उनकी कोशिश की जा रही है। एक ऐसा

दूर उनके आसपास के लोग करते उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से अमेरिका में क्या कहा या विदेशों में वे क्या कहते हैं। इंटरनेट व आधुनिक संचार प्रणाली के इस दौर में आज इस बात के तो कोई मायने ही नहीं रह गये कि आप कौन सी बात कौन से बोलते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बोलें तो यही कोई भी बात पलक झपकते ही पूरे विश्व में एक साथ प्रसारित हो जाती है। फिर क्या अमेरिका तो क्या भारत। दूसरी बात यह कि राहुल ने अमेरिका में ऐसा क्या क्या कहा जो वे यहाँ नहीं करते? भारतीय लोकतंत्र पर मंडराते खतरों पर अकेले राहुल ही चिंता व्यक्त नहीं करते। विपक्ष के और भी तमाम नेता, बुद्धिजीवी, नोबेल पुरस्कार विजेता, शिक्षाविद, लेखक व पत्रकार भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति व लोकतंत्र पर मंडराते खतरों पर चिंता व्यक्त करते ही रहते हैं। और इन सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग सत्ता के इशारे पर या किसी को 'खुद' करने के लिये राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करना चाह रहे हैं उन्हें राहुल गांधी की वे लंबी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देख लेनी चाहिए जिसमें राहुल के पिता राजीव गांधी व दादी इंदिरागांधी को देश की संजका व अखंडता को बचाये रखने के लिये अपनी जानों की कुबली देना पड़ी थी।

मौतिलाह नेहरू से लेकर जवाहर लाल नेहरू, कान्हा नेहरू आदि स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले इसी एक परिवार के संसद थे। ऐसे घराणे से सम्बन्ध रखने वाले राहुल गांधी को वे लोग देशद्रोही साबित करना चाह रहे हैं जिन्हें अन्तः देश में महाना गांधी, भारतीय संविधान और तिरोगे का अग्रगण्य बनें वालों की कमी नहीं? ऐसे लोग राहुल को देशद्रोही साबित करना चाह रहे हैं जिन्हें पूर्वजों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान तो

दूर उनके आसपास के लोग करते उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से अमेरिका में क्या कहा या विदेशों में वे क्या कहते हैं। इंटरनेट व आधुनिक संचार प्रणाली के इस दौर में आज इस बात के तो कोई मायने ही नहीं रह गये कि आप कौन सी बात कौन से बोलते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बोलें तो यही कोई भी बात पलक झपकते ही पूरे विश्व में एक साथ प्रसारित हो जाती है। फिर क्या अमेरिका तो क्या भारत। दूसरी बात यह कि राहुल ने अमेरिका में ऐसा क्या क्या कहा जो वे यहाँ नहीं करते? भारतीय लोकतंत्र पर मंडराते खतरों पर अकेले राहुल ही चिंता व्यक्त नहीं करते। विपक्ष के और भी तमाम नेता, बुद्धिजीवी, नोबेल पुरस्कार विजेता, शिक्षाविद, लेखक व पत्रकार भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति व लोकतंत्र पर मंडराते खतरों पर चिंता व्यक्त करते ही रहते हैं। और इन सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग सत्ता के इशारे पर या किसी को 'खुद' करने के लिये राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करना चाह रहे हैं उन्हें राहुल गांधी की वे लंबी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देख लेनी चाहिए जिसमें राहुल के पिता राजीव गांधी व दादी इंदिरागांधी को देश की संजका व अखंडता को बचाये रखने के लिये अपनी जानों की कुबली देना पड़ी थी।

मौतिलाह नेहरू से लेकर जवाहर लाल नेहरू, कान्हा नेहरू आदि स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले इसी एक परिवार के संसद थे। ऐसे घराणे से सम्बन्ध रखने वाले राहुल गांधी को वे लोग देशद्रोही साबित करना चाह रहे हैं जिन्हें अन्तः देश में महाना गांधी, भारतीय संविधान और तिरोगे का अग्रगण्य बनें वालों की कमी नहीं? ऐसे लोग राहुल को देशद्रोही साबित करना चाह रहे हैं जिन्हें पूर्वजों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान तो

बढ़ती प्राकृतिक विपदाओं का संकट



-संजीव ठाकुर-

आपदा सदैव अक्षयक्षिति घटना होती है। जो मानवीय नियंत्रण से सदैव से बाहर होती है। प्राकृतिक आपदा अत्यंत समय में बिना किसी पूर्व सूचना के घटित होती है, जिससे सूचना जीवन के सारे क्रियाकलापों अवरुद्ध हो कर, जान और माल की बड़ी हानि होती है। आर्थिक तंत्र, विकास नष्ट हो जाते हैं। आपदा की विद्युत्ता, भयानक स्वप्न एक निरंतरता मानव जीवन और समाज और देश को बड़ी हानि पहुंचाकर उस देश की आर्थिक स्थिति में गहरी चोट करते हैं। राष्ट्र को आर्थिक रूप से बहुत पीछे खींच कर ले जाते हैं। आपदा प्रबंधन में जापान से सीख ली जा सकती है। क्योंकि जापान आपदा प्रबंधन में विश्व में अग्रणी देश माना जाता है। जापान स्थिति के ऐसे देश में अवस्थित है, जहां भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं सदैव आती रहती हैं। जापान में आपदा प्रबंधन की अत्याधुनिक तकनीक को याकोहामा रणनीति कहा जाता है। जापान में आपदा प्रबंधन की साल भर नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर एक्सरसाइज की जाती रहती है, एवं आपदाओं पर निरंतर निगरानी तथा नजर रखी जाती एवं इसके निदान के लिए पूर्व से ही सुनिश्चित योजना बनाकर जागरणों को सुरक्षित कर लिया जाता है। भारत को भी इसी तरह आपदा प्रबंधन को अपनाकर अन्य आपदाओं के साथ सतर्क होकर कार्रवाई की जानी चाहिए।



आपदा सदैव अक्षयक्षिति घटना होती है। जो मानवीय नियंत्रण से सदैव से बाहर होती है। प्राकृतिक आपदा अत्यंत समय में बिना किसी पूर्व सूचना के घटित होती है, जिससे सूचना जीवन के सारे क्रियाकलापों अवरुद्ध हो कर, जान और माल की बड़ी हानि होती है। आर्थिक तंत्र, विकास नष्ट हो जाते हैं। आपदा की विद्युत्ता, भयानक स्वप्न एक निरंतरता मानव जीवन और समाज और देश को बड़ी हानि पहुंचाकर उस देश की आर्थिक स्थिति में गहरी चोट करते हैं। राष्ट्र को आर्थिक रूप से बहुत पीछे खींच कर ले जाते हैं। आपदा प्रबंधन में जापान से सीख ली जा सकती है। क्योंकि जापान आपदा प्रबंधन में विश्व में अग्रणी देश माना जाता है। जापान स्थिति के ऐसे देश में अवस्थित है, जहां भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं सदैव आती रहती हैं। जापान में आपदा प्रबंधन की अत्याधुनिक तकनीक को याकोहामा रणनीति कहा जाता है। जापान में आपदा प्रबंधन की साल भर नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर एक्सरसाइज की जाती रहती है, एवं आपदाओं पर निरंतर निगरानी तथा नजर रखी जाती एवं इसके निदान के लिए पूर्व से ही सुनिश्चित योजना बनाकर जागरणों को सुरक्षित कर लिया जाता है। भारत को भी इसी तरह आपदा प्रबंधन को अपनाकर अन्य आपदाओं के साथ सतर्क होकर कार्रवाई की जानी चाहिए।



आपदाओं का पूर्वानुमान अथवा आकलन किया जाना पहले से संभव नहीं हो सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर जांच-सूचना प्रबंधन जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर अत्याधिक सावधानी पूर्वक सोचना तथा विभाग बनाने चाहिए, ऐसे में जापान जैसे देश की तरह आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन सिस्टम को तैयार कर तैयार रखने की आवश्यकता होगी।

भारत को आपदा प्रबंधन जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग को चुनने-दुखरत तथा अत्याधुनिक तकनीक से सुस्त करने की आवश्यकता है। तुर्कनी, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, भूकंप, सूखा बाढ़ के अलावा अब कोविड-19 यानी कोरोना संक्रमण जैसी खतरनाक बीमारियां भारत देश को अपना निशाना बना कर रखा है ऐसे में भारत में मध्यम दर्जे का या निम्न दर्जे का आपदा प्रबंधन सिस्टम किसी भी काम का न रहेगा, एवं इससे भारी जानमाल की हानि होनी है। भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काफी अप्रारंभिक के लिए 1990 में कृषि मंत्रालय को अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट सेल स्थापित किया गया था। 1998 में मध्यम दर्जे के भूकंप तथा 2005 में नासिका के भूस्खलन तथा 1999 में ओडिशा में सुपर साइकलोन तथा 2001 में गुजरात के भूकंप के बाद देश में एक महत्त्वपूर्ण आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की जरूरत को महसूस करते हुए जे.पी. पंत जी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में एक सुसंव्यवस्थित तथा व्यापक सिस्टम तथा विभाग की स्थापना की आवश्यकता प्रविष्टित की गई थी। 2002 में आपदा को देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला

विकास में इंजीनियरों का योगदान



-मनमोहन सिंह-

पूरे भारत में 16 सितंबर को आपदा नियंत्रण-डे मनाया जाता है। यह खास दिन देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले इंजीनियरों के काम को सराहने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दरअसल, यह दिन देश के महान इंजीनियर ह्यू पंजाब में अगर किसी स्थानों के इंजीनियर ही हैं। उन्होंने भारत की प्रगति में बहुमूल्य योगदान दिया। डा. एम. विश्वेश्वरय्या ने देश में कई बंध बनाए। इनमें कृष्णराज सागर बांध, पुणे के खरकवासला जलशय्य में बांध और वल्लिपार में बांध शामिल हैं।

इसी कोशिका 1909 में बनाई गई थी और 1932 में पूरी हुई। उन्होंने मैसूर सरकार के सहयोग से कई कारखाने और शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए। डा. विश्वेश्वरय्या के इन योगदानों के बाद उन्हें देशभर में पहचान मिली। भारत में सिविल इंजीनियरिंग के महान नाटक मोहनगुप्त विश्वेश्वरय्या को श्रेष्ठज्योति के लिए हर साल 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। मोहनगुप्त विश्वेश्वरय्या भारत के पहले सिविल इंजीनियरों में से एक थे, जिन्हें 1955 में भारत सरकार से सम्मानित किया गया था। दुनिया में वे विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों में विविध कर्मोकेतलक, दुर्घटनाएं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कैंसिल इंजीनियरिंग आदि के प्रसार और विकास के साथ-साथ, इंजीनियरों ने दुनिया की स्वीकार की करते हुए मानव जीवन को आरामदायक बनाने के साथ-साथ औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी सुधार लाने। यहां विशाल विभिन्न क्षेत्रों में तमाम नई तकनीकों के विकास को जोड़ने और विकसित करने में इंजीनियरों की शक्ति परिभ्र हो चुकी है जिसके कारण आज के आरामदायक मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

किसी ने एक इंजीनियर से पूछा कि आप इंजीनियर होने पर अपने आप पर गर्व क्यों महसूस करते हैं? उस इंजीनियर ने बड़े ही दिल से यह बात कही और कहा कि जिस प्रकार कानूनी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न क्षेत्र के लोगों की अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था के माध्यम से न्याय दिलाने पर निर्भर करती है और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे व्यापक क्षेत्र से जुड़े लोगों का भविष्य बीमारियों की रोकथाम पर निर्भर करता है उसी तरह एक इंजीनियर ही है जिसकी समृद्धि पर देश और राष्ट्र की समृद्धि का विकास निर्भर करता है। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं उनमें से एक इंजीनियर हूँ। पंजाब में अगर किसी स्थानों के इंजीनियर ही हैं। उन्होंने भारत की प्रगति में बहुमूल्य योगदान दिया है। दिल्ली के बाढ़, पंजाब देश का दूसरा राज्य है जहां सभी घरों उभरनेकोशों को जाति का भेदभावादि विना प्रति माह 2 महीने में 3000600 ग्रुपिंट तक मूस धिवाली बनती का जाती है।

पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, जो पूर्व में पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड था, का कई बार कुशल नवेल्ट इंडी. एच.ए. सहित बहुत ही प्रगतिशील और स्वस्थ इंजीनियरों ने किया था। नवाय सिंघ (आई.सी. ई.सी.) इंजी. एच.आर. साहिया, इंजी. एच. गिल, डॉ.जी. हर्बस ई.ए. इंजी. ए.सी. डी. सी. डी.सी. एन.ए. वसंत, इंजी. के.डी. चौधरी और वर्तमान में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह-सह निदेशक के रूप में इंजी. यलदेश सिंह सरावत के साथीगण विकास और समृद्धि के लिए लक्षित दिना-रत काम करते रहे हैं जिसके कारण बिजली क्षेत्र में कई नए मील के पत्थर स्थापित किए गए हैं। इनके अलावा इंजी. परदेसजी सिंह, इंजी. पी.एस. सताराम और इंजी. संदीप गुप्ता आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं जिन्होंने बिजली क्षेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। लेखक उप सेविध जनसंपर्क विभाग, (सेवाविभूत) पी.एस.पी.सी.एल. हैं।

